भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1119

उत्तर देने की तारीख: 08.02.2021

देश में खोली गई उच्च शिक्षा संस्थाएं

1119. श्री कुंवर दानिश अली:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान देश में खोली गई उच्च शिक्षा संस्थाओं का संख्या कितनी है;
(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2019 में जारी नई शिक्षा नीति के प्रारूप में अनुमान लगाया गया कि नीति के प्रस्ताव के उपयुक्त क्रियान्वयन के लिए शिक्षा के बजटीय आवंटन को अगले 10 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत बढाया जाय, लेकिन बजट 2020-21 में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में पांच प्रतिशत से भी कम हुई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना केंद्र और राज्य सरकारों और संबंधित नियामक निकायों के क्षेत्राधिकार में है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के तहत, नए खोले गए उच्च शिक्षण संस्थानों की सूचना का एकत्रीकरण और रखरखाव नहीं किया जा रहा है। हालांकि, पिछले दस वर्षों के दौरान देश में सर्वेक्षण के उद्देश्य से एआईएसएचई पोर्टल पर पंजीकृत उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**	**2011**	**2010**
संस्थानों की संख्या	55165	51649	49964	52559	51793	51534	49021	47757	46620	44690

(ख) और (ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 29 जुलाई, 2020 को घोषित की गई है जिसमें कहा गया है कि यह नीति शैक्षिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के प्रति प्रतिबद्ध है क्योंकि हमारे युवा लोगों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की तुलना में समाज के भविष्य के लिए अन्य कोई बेहतर निवेश नहीं है। उत्कृष्टतायुक्त शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने और इस राष्ट्र और इसकी

अर्थव्यवस्था को होने वाले अनेक लाभों को प्राप्त करने के लिए, यह नीति एकमत से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का समर्थन करती है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि की परिकल्पना की गई है। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि यथाशीघ्र जीडीपी के 6 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

घ): एनईपी 2020 के अनुसार, सरकार द्वारा शिक्षा के मानक में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:

I. चिकित्सा और विधि शिक्षा को छोड़कर शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकल समग्र शीर्ष निकाय भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई)

II राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) केंद्रीय बजट 2021 में इस योजना के तहत पोस्टएजुकेशन अप्रेटिसशिप इंजीनियरिंग और डिप्लोमा धारकों के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 3000 करोड से अधिक की घोषणा की गई है।

III बहु प्रविष्टि / निकास विकल्पों के साथ समग्र बहुविषयक शिक्षा।

IV अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना।

V. बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना।

VI नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना। केंद्रीय बजट 2021 में 5 वर्षों में 50000 करोड रूपए के परिव्यय की घोषणा कीगई है। यह सुनिश्चित करेगा कि देश के समग्र अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मजबूत जाए।

VII जीईआर बढ़ाने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार।

VIII शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण।

IX व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगा।

X मेंटरिंग के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना।

XI शिक्षण, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (एनईटीएफ) का निर्माण।

XII चेक और बैलेंस के साथ कई तंत्र उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण का मुकाबला करेंगे और रोकेंगे।

XIII गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर समग्र ध्यान लाने के लिए समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मजबूत करना।

XIV. लद्दाख में सुलभ उच्च शिक्षा के लिए केंद्रीय बजट 2021 में लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालयस्थापित करने के प्रस्ताव की घोषणा की गई है।

XV. केंद्रीय बजट 2021 में प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जा रही इंटरनेट पर शासन और नीति संबंधित सम्पदा को सक्षम करने के लिए एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनटीएलएम) घोषित किया गया है।